मुख्यमंत्री ने जयपुर में स्पोर्ट्स हब बनाने का एम.ओ.यू. किया

इसमें स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल चिकित्सा व अन्य खेल सुविधायें विकसित होंगी

- मुख्यमंत्री भजनलाल की, नैशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैल्थ एंड केयर एक्सलैंस के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार के साथ, राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली रोगी देखभाल सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य दिशा निर्देश तथा नई स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को शुरु करने पर चर्चा हुई।
- स्पोर्ट्स हब राजस्थान रॉयल्स की मालिक कम्पनी विकसित करेंगी।

जयपुर, 18 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यू.के. रोड शो के दूसरे दिन नेशनल इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सलैंस (एन.आई.सी.ई.) के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार ह्यू मैकगायर से मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा में एन.आई.सी.ई. के काम पर व्यापक चर्चा की, जिसमें व्यावहारिक मार्गदर्शन के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने में चिकित्सकों का समर्थन, नई स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का स्वतंत्र मूल्यांकन और करदाताओं के लिए मूल्य सुनिश्चित करते हुए रोगी परिणामों में सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य देखभाल दिशानिर्देश विकसित करने और नवीन स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों को शुरू करने में संभावित सहयोग पर भी चर्चा की।

मुख्यमंत्री शर्मा व उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने पार्लियामैंट हाउस लंदन के सामने लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रृद्धांजलि दी।

इसके अलावा, राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के मालिक, रॉयल मल्टीस्पोर्ट प्रा.लि. के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। रॉयल मल्टीस्पोर्ट और प्रतिनिधिमंडल के बीच जयपुर शहर को स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। इसमें स्टेडियम, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, खेल चिकित्सा व अन्य खेल सुविधाएं होंगी।

लंदन में "राइजिंग राजस्थान" इंवैस्टर मीट में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों की तारीफ करते हुए कहा कि वे जिस तरह से राइज़िंग राजस्थान को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इससे निश्चित है कि हम विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की एक मज़बूत नींव रख रहे हैं। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री जितने भी देशों में जा रहे है,वहाँ राजस्थान में निवेश के लिए व्यवसायियों में अत्यधिक उत्साह देखने का मिल रहा है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी उपस्थित निवेशकों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत औऱ राजस्थान दुनिया का आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्र बनने को तैयार है। उन्होंने निवेशकों से ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की अपील करते हुए कहा कि वे भी राजस्थान आयें औऱ राजस्थान की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनें।

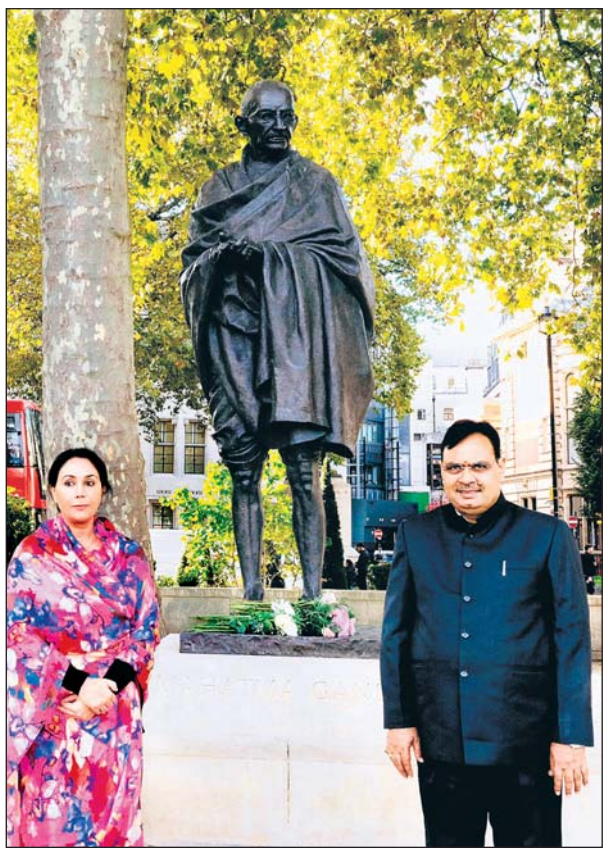

लन्दन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट हाउस के सामने महात्मा गाँधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रृद्धांजलि दी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को प्रवासी राजस्थानी समुदाय से संवाद किया। उन्होंने कहा कि यू.के. के प्रवासी समुदाय की उद्यिमता राजस्थान में व्यापार को प्रोत्साहित कर नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। दिया कुमारी ने "राइजिंग राजस्थान" के तहत, प्रवासी राजस्थानी समुदाय से अनुरोध किया कि वे राज्य में व्यापारिक अवसरों का अन्वेषण करें और नवाचार तथा निवेश के माध्यम से विकसित राजस्थान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ।

मोदी शनिवार को कर्मयोगी सप्ताह का शुभांरम करेंगे

नयी दिल्ली 18 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को यहां डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में कर्मयोगी सप्ताह – राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी और तब से इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार में निहित भविष्य के अनुकूल सिविल सेवा की कल्पना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह (एन.एल.डब्ल्यू.) अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। यह पहल सीखने और विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी। एन.एल.डब्ल्यू. का लक्ष्य "एक सरकार" का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ता अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे और उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में काम करने में मदद करेंगे।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5 और गिरफ्तार

इन लोगों पर साजिश में शामिल होने व लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है

- पुलिस सूत्रों के अनुसार, नितिन और राम कनौजिया आरेपियों के मुखिया थे। उन्होंने गोली चलाने वालों को हथियार पहुँचाये तथा आरोपियों को पैसे तथा लोकल मदद भी उपलब्ध कराई।

मुंबई, 18 अक्टूबर। मुंबई में बीते दिनों एन.सी.पी. नेता और मायानगरी के चर्चित चेहरे बाबा सिद्दीकी की शुक्रवार को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने केस में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनपर बाबा सिद्दीकी की साजिश में शामिल होने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। पुलिस ने इस केस में 5 नए आरोपियों को गिरफ़्तार किया है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नितिन और राम कनौजिया इन सभी आरोपियों का मुखिया था। इसी मॉड्यूल ने गोली चलाने वाले आरोपियों को हथियार पहुंचाया था। पुलिस की तरफ से ऐसा बताया गया है कि दोनों शूटर धर्मराज कश्यप और शिवकुमार के साथ भी संपर्क में थे। कर्जत में आरोपियों के साथ में 2 महीने तक रहे भी थे। इन्होंने आरोपियों को पैसे और लोकल मदद भी मुहैया कराई थी।

पुलिस सूत्रों की जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी जिशान अख्तर और शुभम लोनकर के भी संपर्क में थे। गिरफ्तार आरोपी नितिन पर 3 मामले दर्ज है, मर्डर, हाफ मर्डर और आर्म्स एक्ट के। वहीं, राम कुमार पर भी कुछ आरोप दर्ज हैं। इन आरोपियों को हथियार सितंबर महीने के आस पास दिया गया था।

बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर बीते दिन बेटे जीशान सिद्दीकी ने बयान जारी किया था। उन्होंने लिखा था- "मेरे पिता ने गरीब निर्दोष लोगों के जीवन और घरों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। आज मेरा परिवार टूट गया है, लेकिन उनकी मौत का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से इसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, मेरे परिवार को न्याय चाहिए।"

तमिलनाडू में राज्यपाल और...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"पूरे देश में तमिल भाषा को आगे बढ़ाने के लिये क्या किया।"

राज्य में आयोजित "हिन्दी माह" के समारोहों एवं कार्यक्रमों के समापन के अवसर पर हिन्दी भाषा के बारे में अपने कथनों के माध्यम से, राज्यपाल ने भाषा-विवाद के गड़े मुर्दे उखाड़े हैं।

उत्तेजित हो चुके मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक्स पर पी.एम.ओ. को टैग करते हुये माँग की कि किसी गैर-हिन्दी भाषी राज्य में इस प्रकार के हिन्दी-माह नहीं मनाये जायें। उन्होंने हिन्दी-माह के आयोजनों के समापन समारोह के साथ ही, चेन्नई दूरदर्शन के स्वर्ण जयन्ती समारोहों की भी निन्दा की।

स्टालिन ने कहा, "भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। एक बहुभाषी राष्ट्र के किसी गैर-हिन्दी भाषी राज्य में हिन्दी-माह का आयोजन अन्य भाषाओं को छोटा करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है।" उन्होंने आगे कहा, इसलिये मेरा सुझाव है कि गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में इस प्रकार के हिन्दी-केन्द्रित आयोजनों से बचा जाना चाहिये तथा इनके बजाय, संबंधित राज्यों में स्थानीय भाषा माह के आयोजन प्रोत्साहित किये जाने चाहिये।" हिन्दी भाषा के बारे में स्टालिन के इस जबरदस्त बयान से एक्स पर विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है तथा इस बिन्दु को लेकर स्टालिन पर संदेह के जबरदस्त प्रहार हो रहे हैं कि स्टालिन एक यूरोपियन भाषा को लेकर सहज, लेकिन एक भारतीय भाषा के खिलाफ क्यों हैं। अब, इस सब के बावजूद, बहुत से द्रमुक नेताओं, जिनमें स्टालिन के स्वर्गीय पिता एम. करूणानिधि भी शामिल हैं, के ऐसे स्पष्टीकरण भी आ रहे हैं कि राज्य किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, किन्तु किसी भाषा के थोपे जाने का विरोध कर रहा है। हिन्दी को दिया जा रहा जरूरत से ज्यादा महत्व तथा इसे आक्रामक रूप से आगे बढ़ाया जाना ही एक ऐसी चीज़ है, जिसका विरोध यह राज्य पिछले कई दशकों से करता आ रहा है।

सिनवार की हत्या कर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में नेतन्याहू कई बड़े लक्ष्य निहित हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि उनके नेतृत्व में इज़रायल हर उस व्यक्ति, देश या संस्था को सजा दे सकता है, चाहे सामने कोई भी हो। नेतन्याहू हमास के खिलाफ युद्ध बंद करने का भारी दबाव था। अमेरिका जैसे सच्चे दोस्त ने भी युद्ध बंद करने का दबाव डाला था। इज़रायल विरोधी आतंकी संगठनों को नेतृत्व विहीन कर देना इन संगठनों के मसीहा ईरान के लिए भारी झटका है। इज़रायल ने जब हिज्बुल्लाह के चीफ को मार दिया था तब ईरान ने इज़रायल पर हमला भी किया। सभी को उम्मीद थी कि इज़रायल जवाब देगा, पर इज़रायल ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है कि इज़रायल ने अपनी प्राथमिकता तय कर ली है। ईरान से बदला लेने की बजाय उसका सारा फोकस पड़ौस के आतंकी संगठनों का खात्मा करने पर है। इससे उसकी ताकत बढेगी और वह अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करने की स्थिति में आ सकता है। इन आतंकी संगठनों पर निर्णायक जीत से इन संगठनों के प्रति ईरान के समर्थन का पर्दाफाश भी हो सकता है। अभी तो यही इतंज़ार है कि सिनवार की हत्या पर ईरान क्या प्रतिक्रिया देगा। ईरान दोबारा इज़रायल पर हमला करेगा इसकी संभावना तो नहीं लगती है।

'बाल विवाह जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है'

सुप्रीम कोर्ट ने देश में हो रहे बाल विवाहों पर तीखी टिप्पणी की

- मुख्य न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीशों की बैंच ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कानून के प्रभावी कार्यान्वयन पर दिशा निर्देश जारी किये।

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर। बाल विवाह के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को सख्त टिप्पणी की और कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को पर्सनल लॉ के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि बाल-विवाह और अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है।

देश में बाल विवाह में वृद्धि का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह की रोकथाम पर कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जज जेबी पारदीवाला और जज मनोज मिश्रा की पीठ ने देश में बाल विवाह रोकथाम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश में कहा गया कि इस तरह के विवाह नाबालिगों की जीवन चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हैं। प्राधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा अपराधियों को अंतिम उपाय के रूप में दंडित करना चाहिए।

पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह रोकथाम कानून में कुछ खामियां हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को रोकने और समाज से उनके उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का स्थान लिया।

पीठ ने कहा, ये रणनीति अलग-अलग समुदायों के लिए बनाई जानी चाहिए। कानून तभी सफल होगा जब बहु-क्षेत्रीय समन्वय होगा। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है।

जुलाई में जारी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन रिपोर्ट ने बाल विवाह से निपटने के लिए असम सरकार के प्रयासों की सराहना की। रिपोर्ट में कहा गया कि कानूनी कार्रवाई के जरिए असम में बाल विवाह के मामलों को कम किया है। 2021-22 और 2023-24 के बीच राज्य के 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81 प्रतिशत की कमी आई है।

प्रधानमंत्री 27 को जयपुर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसे लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार काम कर रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर जयपुर में रोशनी कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे।

इस कार्यक्रम के लिए राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग की ओर से सम्पूर्ण व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इसलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ विधिवत् रूप से ई.आर.सी.पी. का उद्घाटन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की सभा के लिए वाटिका के पास दादिया गांव में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इससे पहले इसी स्थान पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई थी। आम चुनाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जयपुर आ रहे हैं।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दुष्कर्म किया। फिर, दस मार्च, 2019 को अभियुक्त उसे कॉलेज के बाहर से गाड़ी में बैठाकर ले गया। इस समय अभियुक्त की बहन और जीजा भी बस में मौजूद थे। अभियुक्त की बहन की ओर से पिलाए गये पानी से वह अर्ध बेहोशी में चली गई। इसके कुछ देर बाद वो लोग उसे बस से उतार कर चले गए। रिपोर्ट में कहा गया कि 17 जून, 2019 को उसके पिता के पास थाने से फोन गया कि अभियुक्त ने थाने में शिकायती पत्र दिया है और उसमें शादी का प्रमाण पत्र भी है।

तब पीड़िता ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

प्रधानमंत्री मोदी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सदस्य देशों के अपने समकक्षों और आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं।

रूस इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीक शामिल हैं। सऊदी अरब, ईरान, इथियोपिया, मिस्त्र, अर्जेंटीना और संयुक्त अरब अमीरात इसके नए सदस्य हैं।

इससे पहले 8 जुलाई को पीएम मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा पर रूस गए थे। यहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया था।

एन.डी.ए. ने झारखंड में सीटों के बंटवारे का फार्मुला तय किया

फार्मुला के अनुसार भाजपा 68, ऑल झारखण्ड स्टूडैन्ट्स यूनियन 10, जदयू 2 तथा एल.जे.पी. 1 सीट पर लड़ेंगे

- माना जा रहा है कि यह फार्मूला लगभग तय हो गया है। वैसे घटक दलों के साथ भाजपा की चर्चा के दौर अभी जारी रहेंगे।

रांची, 18 अक्टूबर। झारखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही राजनीति गरमा गई है। एन.डी.ए. में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि एल.जे.पी. एक और जनता दल यूनाइडेट दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के बीजेपी प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, "सीटों पर चर्चा हो रही है आगे भी चर्चा जारी रहेगी। अभी तक की चर्चा में ऑल झारखंड स्टूडैंट्स यूनियन (ए.जे.एस.यू.)10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी... जेडीयू 2 सीटों और एल.जे.पी. 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा बाकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं।" ए.जे.एस.यू. के नेता सुदेश महतो ने कहा कि पूरे राज्य की भावना है कि दोनों दल साथ में चुनाव लड़ें। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार निजी हित में कितनी दूर जा सकती है यह पूरे भारत देश में एक उदाहरण है।

झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। राज्य में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होगा जब कि दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी।हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, "सीट बंटवारे के समझौते के मुताबिक झारखंड में राजग की सहयोगी ए.जे.एस.यू. पार्टी 10 सीट पर, जद(यू) दो और लोजपा (रामविलास) एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। यह लगभग तय है।"

शर्मा ने कहा, ए.जे.एस.यू. सिल्ली, रामगढ़ , गोमिया, ईचागढ़ , मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहरदगा और मनोहरपुर से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि जद(यू) जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ से जबकि लोजपा (रामविलास) चतरा से चुनाव लड़ेगी। शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो की मौजूदगी में यह टिप्पणी की। समझौते के अनुसार, भाजपा 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शर्मा ने कहा कि हालांकि चर्चा जारी है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

आर.जे.एस. भर्ती परीक्षा...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके साथ ही, अदालत ने मामले में हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी जवाब देने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सी.जे.आई.) डी. वाय. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश अनंत मिश्रा व अन्य की याचिकाओं पर सयुंक्त सुनवाई करते हुए दिया।

याचिकाओं में कहा कि, आर.जे.एस. की मुख्य परीक्षा का परिणाम एक अक्टूबर को घोषित किया गया और चार अक्टूबर को उन्हें उत्तर पुस्तिका के नंबर पता चले, जिससे उन्हें पता चला कि उनके अंग्रेजी विषय में बहुत ही कम अंक आए। जबकि, वे नैशनल लॉ युनिवर्सिटी से पास हुए हैं और कुछ अभ्यर्थियों का माध्यम अंग्रेजी रहा है। लेकिन भर्ती के अंग्रेजी निबंध लेखन की परीक्षा में उन्हें ज़ीरो, एक, दो, तीन व चार अंक दिए हैं, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन मनमाने तरीके से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगते हुए 15 अंक से कम वाली उत्तर पुस्तिकाओं को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि, आर.जे.एस. के 222 पदों के लिए हुई मुख्य परीक्षा में 3000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इनमें से 638 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है।

निज़ामुद्दीन उर्स के लिए 82 पाक ज़ायरीनों को वीज़ा

इस्लामाबाद/नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर। राष्ट्रीय राजधानी में हजरत निजामुद्दीन औलिया के वार्षिक उर्स में शामिल होने के लिए 82 पाकिस्तानी जायरीनों को 19-25 अक्टूबर तक वैध भारतीय वीजा दिया गया। पाकिस्तानी पत्रकार शौकत पिराचा के अनुसार, पाकिस्तानी जायरीन शनिवार को वाघा सीमा पार कर भारत में प्रवेश करेंगे।

शिवसेना (शिन्दे) को टिकट देने को तैयार नहीं भाजपा कार्यकर्ता

भाजपा ने कार्यकर्ताओं के रोष पर काबू पाने के लिए कड़े कदम उठाये

- भाजपा कार्यकर्ता नागपुर के पास रामटेक तथा चन्द्रपुर की वरोरा सीट शिन्दे सेना को नहीं देना चाहते। भाजपा ने पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी को 6 साल के लिए निलम्बित किया। पर रेड्डी ने पूरे मामले में भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखा।

महाराष्ट्र, 18 अक्टूबर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में सभी सीटों पर एक चरण में वोटिंग होगी। इस बीच, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने नागपुर की रामटेक विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने यहां से पूर्व निर्दलीय विधायक आशीष जयसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक मलिकार्जुन रेड्डी ने इस उम्मीदवारी को लेकर बगावत शुरू कर दी है, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया।

हालांकि, मल्लिकार्जुन रेड्डी अब भी खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं और उन्होंने निलंबन वापस लेने व आशीष जयसवाल को उम्मीदवार नहीं बनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र तक लिख दिया है। भाजपा से निलंबित पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी ने कहा कि रामटेक क्षेत्र में वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मजबूत कैसे करेंगे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं, शिंदे गुट को क्यों स्वीकार करेंगे, हमेशा के लिए उन्हें कैसे मुख्यमंत्री मानेंगे, वह एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन गए हैं, हमारे विधायक ज्यादा आते हैं, अभी हमारे विधायक ज्यादा आएंगे तो मुख्यमंत्री शिंदे जी को कैसे बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस दिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भेजा है। इस तरह की बगावत महाराष्ट्र की सिर्फ एक सीट को लेकर नहीं है। महाराष्ट्र की, चंद्रपुर स्थित वरोरा विधानसभा सीट में भी भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। भाजपा के कार्यकर्ता अपना विरोध जताने के लिए नागपुर के विदर्भ कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंच गए और संगठन मंत्री के सामने जमकर नारेबाजी की। इन लोगों की मांग है कि चंद्रपुर की वरोरा सीट शिवसेना को नहीं देनी चाहिए। इस सीट पर भाजपा का पक्ष काफी मजबूत है, इसलिए पार्टी को इस सीट से उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, जबकि वरोरा की सीट शिवसेना के कोटे में जाने की खबर है।

आप नेता सत्येन्द्र जैन को जमानत मिली

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर। दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सत्येन्द्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) की ओर से उनके खिलाफ दर्ज धन-शोधन मामले में शुक्रवार को नियमित जमानत दे दी।

राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद जैन को कई शर्तों पर जमानत दी।

अदालत ने लंबे मुकदमे और करीब 18 महीने की कैद को देखते हुए, उनकी नियमित जमानत याचिका स्वीकार की। अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत दी। इसके अलावा, मामले से संबंधित गवाहों से संपर्क न करने या उन्हें प्रभावित न करने और पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर न जाने का भी उन्हें निर्देश दिया गया है।

कांग्रेस ने महाराष्ट्र में दस हजार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरकार को दिया गया है।"

उन्होंने किसी का नाम लिये बिना कहा, "महाराष्ट्र स्टेट रोड डवलमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.एस.आर.डी.सी.) ने महाराष्ट्र में विभिन्न राजमार्ग प्रोजेक्टों, जैसे विरार अलीबाग मल्टीमोडल कॉरिडोर (एम.एम.सी.) पुणे रिंग रोड (पी.आर.आर.) आदि के लिये प्राइस बिड खोली थीं। एम.एस.आर.डी.सी. का एक नियम था कि एक बिडर को केवल दो पैकेज तक ही मिलेंगे, लेकिन इस नियम को बदल दिया गया, और इसे बदलने के लिये आठ प्रोजेक्टों को टनल प्रोजेक्ट के रूप में परिभाषित कर दिया गया तथा इसके लिए पात्रता-शर्तें अलग प्रकार की कर दी गईं। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि अधिकांश पैकेज कुछ गिनी-चुनी फर्मों को ही दिये जा सकें।"

खेड़ा ने आरोप लगाया कि एम.एस.आर.डी.सी. ने इन टनल प्रोजेक्टों के लिये पूर्व-पात्रता-शर्तें (प्री-क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया) बदल दीं, जबकि इसके पूर्ववर्ती प्रोजेक्टों, जैसे "मिसिंग लिंक एंड मुम्बई नागपुर" में ऐसा नहीं किया गया था, जहाँ टनल के व्यास और लम्बाई के लिये प्री-क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया व्यास के लिए 50 प्रतिशत तथा लम्बाई के लिए 20 प्रतिशत रखा गया था तथा ऐसा ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इन्डिया (एन.एच.ए.आई.) मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हाईवेज़ (एम.ओ.आर.टी.एच.), बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बी.आर.ओ.), नैशनल हाईवेज़ एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.एच.आई.डी.सी.एल.) तथा अन्य करते हैं।

खेड़ा ने कहा कि यह सी.ए.जी., मीडिया, अदालत तथा महाराष्ट्र के मतदाताओं के लिए जगाने वाली घंटी (वेक-अप-कॉल) है।

खेड़ा ने कहा, "जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता आयेगी, तो इस घोटाले में लिप्त कोई भी व्यक्ति, चाहे वह दिल्ली में बैठा हो या मुम्बई के मन्त्रालय में, बख्शा नहीं जायेगा।

खेड़ा ने पूछा, "क्या प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण तथा सड़क यातायात एवं राजमार्ग विभाग के केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी इस चुनावी बॉन्ड घोटाला के लिये जवाबदेह बनाये जायेंगे, जिसमें महाराष्ट्र की जनता से हजारों करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की गई है।

आखिर आदमखोर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साथ पूरे जंगल को घेरेंगे और अपने स्तर पर पैंथर को पकड़ने के लिए घेरा डालेंगे। इसके लिए शुक्रवार सुबह से ही ग्रामीण जुटने लगे थे, इस बीच टीम ने पैंथर को शूट कर दिया। गांव वालों ने कहा कि सबसे पहले तो यह देखने की जरूरत है कि यही आदमखोर पैंथर है या नहीं। अगर ये आदमखोर नहीं है तो यहां पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और पिंजरे लगाए जाएं।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्टीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908